भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 685

बुधवार, 06 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में औद्योगिक विकास

685. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की चेन्नई में 7-8 जनवरी, 2024 को आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 2024 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत की बड़ी कंपनियों के प्रवेश के लिए संबद्ध करने और समर्थन देने की कोई योजना है और प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में तमिलनाडु को विनिर्माण केन्द्र होने के साथ-साथ समग्र ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जबरदस्त विस्तार की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भारत में विशेषकर तमिलनाडु में एआई, एमएल, डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, फोटोनिक्स, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, यूएवीएस और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने और प्रतिभा के विकास के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति बनाने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): अब तक, वैश्विक निवेशक बैठक, 2024 को सहायता प्रदान करने के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (घ): उद्योग की स्थापना करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करते हैं। भारत सरकार विभिन्न उपायों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। डीपीआईआईटी, औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास हेतु स्कीमों को कार्यान्वित करता है और विभिन्न नीतिगत उपाय/पहलों को लागू करता है, जैसे निवेश प्रोत्साहन हेतु स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, औद्योगिक अवसरंचना उन्नयन स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर, स्टार्टअप इंडिया, फुटवियर, चमड़ा और सहायक

सामग्री विकास कार्यक्रम तथा भौगोलिक संकेतकों से प्रोत्साहन हेतु पहल, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) इत्यादि।

(ग) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), बहु-विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएम-आईसीपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस मिशन के तहत, उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में देशभर में राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवप्रयोग केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए गए हैं, जिनमें एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम, रोबोटिक्स, यूएवी आदि शामिल हैं। इन केंद्रों में से एक, आईआईटीएम प्रवर्तक प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान, आईआईटी मद्रास के सेंसर, नेटवर्किंग, एक्यूएटर और कंट्रोल के प्रौद्योगिकी वर्टिकल के अंतर्गत स्थापित किया गया है। टीआईएच के अधिदेश के कुछ प्रमुख घटकों में, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास और कौशल विकास शामिल हैं। इन घटकों का उद्देश्य, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम, रोबाटिक्स, एआर और वीआर आदि सहित उन्नत और उभरते प्रौद्योगिकी वर्टिकल के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और टेक्नोक्रेट्स को तैयार करने के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

*****